आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)

24.06.2025 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- देहरादून में आज से श रू होगा तीन दिवसीय भारतीय संरक्षण सम्मेलन–2025, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे उद्घाटन।

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया।

- देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल 'नंदा–सुनंदा' आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय बालिकाओं की शिक्षा को दे रही नया जीवन, अब तक 38 बालिकाओं को करीब चौदह लाख रुपए की सहायता दी गई।

- त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की रोक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया।

भारतीय संरक्षण सम्मेलन

भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में आज से तीन दिवसीय भारतीय संरक्षण सम्मेलन– 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे।

सम्मेलन में भारत और वैश्विक दक्षिण के 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें वैज्ञानिक, शोधकर्ता, वन सेवा अधिकारी, छात्र, गैर–सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा नीति निर्माता मौजूद रहेंगे। ये सभी भारत की जैव विविधता से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार करेंगे।

भारतीय संरक्षण सम्मेलन की शुरुआत 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हुई थी। तब से यह मंच संरक्षण विज्ञान और युवा जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले समावेशी संवाद का प्रमुख माध्यम बन चुका है।

इस बार सम्मेलन में 17 विषयों पर आधारित सत्र, मौखिक वार्ताएं, पोस्टर प्रस्तुतिकरण, स्पॉटलाइट व्याख्यान और 10 कार्यशालाएं आयोजित होंगी। खास आकर्षण के रूप में टेकब्रिज की शुरुआत की जा रही है, जो क्षेत्रीय कार्यों के लिए नवीन वन्यजीव तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित करेगा। यह सम्मेलन छात्रों और शोध के प्रारंभिक चरण में लगे युवाओं को विशेषज्ञों से जुड़ने और अपने कार्यों को साझा करने का भी अवसर प्रदान करेगा।

मध्य क्षेत्रीय परिशद बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने सीमा सड़क संगठन के माध्यम से और अधिक सहयोग, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गांवों के विकास, भारत नेट योजना और सैटेलाइट आधारित संचार सेवाएं शुरू करने की मांग की।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्रीय अनुदान एकमुश्त देने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर संचालन के लिए अतिरिक्त सहयोग, राज्य में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान और अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।

मुख्यमंत्री ने 2026 में प्रस्तावित नंदा राजजात यात्रा और 2027 के कुंभ मेले के भव्य आयोजन के लिए भी केंद्र से सहायता का अनुरोध किया।

स्वास्थ्य सुविधा समीक्षा

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। क्लेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में उन्होंने अस्पतालों में निर्माणाधीन ब्लड बैंक, आईसीयू और मैकेनिकल पार्किंग के कार्यों को तेजी से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

उपराश्ट्रपति प्रवास

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज तीन दिवसीय प्रवास पर नैनीताल पहुंचेंगे। इस दौरान वे कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह और शेरवुड कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

नंदा–सुनंदा' प्रोजेक्ट

देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर संचालित प्रोजेक्ट 'नंदा–सुनंदा' आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय बालिकाओं की शिक्षा को नया जीवन दे रहा है। कलक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ने कल पांच छात्राओं को कुल 1 लाख 65 हजार 800 रुपये के चेक वितरित किए। अब तक इस प्रोजेक्ट के तहत जिले में करीब 14 लाख रुपये की मदद से 38 बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित किया जा चुका है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनके प्रति नजरिए को बदलना है। उन्होंने कहा कि यह एक निरंतर प्रयास है, जो भविष्य में भी चलता रहेगा। उन्होंने बालिकाओं से पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन उनकी शिक्षा में हर संभव सहयोग देगा।

रोक

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक की आरक्षण प्रक्रिया पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की रोक के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।

राज्य निर्वाचन आयोग, ने कल शाम अधिसूचना जारी कर आज से प्रस्तावित नामांकन और चुनाव संबंधी अन्य कार्यवाही को रोक दिया है। यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है।

उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई में कहा था कि पंचायत चुनाव 2025 के लिए आरक्षण और सीटों के आवंटन संबंधी नियमों को राज्य सरकार द्वारा अभी तक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी कार्यवाही अगले आदेश तक नहीं की जाएगी।

इस बीच, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार आज उच्च न्यायालय में चुनाव की अधिसूचना पेश करेगी। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने यह जानकारी दी।

एक दिवसीय कार्यशाला

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम एन.एफ.डी.सी., इंडिया सिने हब और उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आज देहरादून में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया कि कार्यशाला का विषय "डेवलपमेंट इन फिल्मिंग इकोसिस्टम इन उत्तराखण्ड" रखा गया है।

कार्यशाला में एन.एफ.डी.सी. और इंडिया सिने हब के अधिकारी भारत सरकार की फिल्म निर्माण से जुड़ी नीतियों और योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण देंगे। साथ ही, उत्तराखण्ड सरकार की हाल ही में लागू की गई फिल्म नीति 2024 की जानकारी भी दी जाएगी।

इस कार्यशाला में फिल्म निर्माता, निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर, फिल्म एडीटर, होटल उद्योग और टूर एंड ट्रैवल सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम के स्थगन की ख़बर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हिन्दुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है। अमर उजाला ने लिखा है – अदालत का फैसला आने तक चुनाव प्रक्रिया टली।

त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस खबर के साथ नवोदय टाइम्स लिखता है– सरकार को राहत नहीं, आज भी सुनवाई। दैनिक जागरण ने लिखा है– पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक हटाने को हाईकोर्ट पहुंची सरकार।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को भी सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। नवोदय टाइम्स ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है– नीतिगत प्रावधानों में उत्तराखंड को मिले विशेष छूट। अमर उजाला ने लिखा है – सीएम ने मध्य क्षेत्रीय बैठक में उठाए मुद्दे, नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता मांगी।

प्रदेश के चार जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अर्लट जारी किया गया है। यह समाचार भी लगभग सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है।